वर्ष 27 अंक 211
पृष्ठ 18+4=22
नई दिल्ली, मंगलवार
14 फरवरी 2017
राजधानी
मूल्य ₹ 5.00

विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार

दैनिक जागरण

बिना इजाजत रोड शो करने पर राहुल के खिलाफ मुकदमा 11

तबला वादक संदीप दास ने जीता ग्रैमी अवार्ड 17

www.jagran.com

दिल्ली • उत्तर प्रदेश • मध्य प्रदेश • हरियाणा • उत्तराखण्ड • बिहार • झारखंड • पंजाब • जम्मू-कश्मीर • हिमाचल प्रदेश • पश्चिम बंगाल से प्रकाशित

सरोकार

एनसीआर में एक नीति से जारी होंगे प्रदूषण प्रमाणपत्र

नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर में जल्द एक समान नीति से प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से इस बाबत ऑडिट रिपोर्ट मंगवा ली है। • पेज 4

अंदर पढ़ें

कनॉट प्लेस हादसे में चार इंजीनियर निलंबित

नई दिल्ली : कनॉट प्लेस में 10 दिनों में दूसरी बार छत गिरने से एनडीएमसी की तंद्रा टूटी। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद चेयरमैन ने सोमवार को चार इंजीनियरों को निलंबित कर दिया। • पेज 2

शशिकला पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

नई दिल्ली : आय से अधिक संपत्ति मामले में अन्नाद्रमुक महासचिव शशिकला पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला करेगा। फैसला खिलाफ आया तो वह तमिलनाडु का सीएम नहीं बन सकेंगीं। • पेज 13

jagran.com वेबसाइट पर पढ़ें

शशिकला का रहस्योद्घाटन

...तो इसलिए जयललिता के निधन की रात सीएम नहीं बनीं शशिकला

विधवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन एक हजार रुपये बढ़ी

उपराज्यपाल अनिल बैजल

वीके शुक्ला • नई दिल्ली

देश में सबसे अधिक पेंशन देने की दिल्ली सरकार की योजना को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद विधवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन में 1000 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। इस बारे में दिल्ली सरकार जल्द अधिसूचना जारी करेगी। एलजी अनिल ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए पारदर्शिता अपनाने के दिए निर्देश हैं, ताकि गलत लोग फायदा नहीं उठा सकें। विधायकों व निगम पार्षदों को पेंशन की सिफारिश करने की सुविधा बरकरार रहेगी।

कैबिनेट ने 6 जनवरी को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद स्वीकृति के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया था। प्रस्ताव में दिव्यांग एवं विधवा की पेंशन 1500 से बढ़ाकर 2500 रुपये की गई है। वहीं 60 वर्ष से 69 वर्ष तक के वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन एक हजार से बढ़ाकर दो हजार रुपये और 69 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 1500 से 2500 रुपये कर दी गई है।

सड़कों से दूर रहीं डेढ़ लाख कैब

दिल्ली-एनसीआर में एप बेस्ड टैक्सियां नहीं चलने से लोगों को हुई काफी परेशानी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : एप बेस्ड कैब चालकों की हड़ताल से सोमवार को दैनिक कैब यात्रियों को काफी मुश्किलें आईं। सुबह और शाम को एप बेस्ड कैब सेवा पूरी तरह ठप होने के कारण यात्रियों ने ऑटो, मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहनों का सहारा लिया। इस कारण उन्हें दफ्तर पहुंचने और वहां से घर लौटने में परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, यात्रियों की सुविधा के लिए एप बेस्ड कैब प्रदाता कंपनियां ऑटो, शटल और बाइक से यात्रा करने के सुझाव एप और मैसेज के माध्यम से देतीं नजर आईं। इस बीच, चार दिन से हड़ताल पर चल रहे एप बेस्ड कैब चालकों और कंपनियों के बीच जारी बातचीत के कारण मंगलवार को कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है।

हड़ताल का आह्वान करने वाले सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के पदाधिकारियों ने दावा किया कि चौथे दिन दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर डेढ़ लाख से अधिक एप बेस्ड कैब नहीं चलीं। हालांकि, कुछ कैब चलने के सवाल पर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रवि राठौर ने बताया कि ये कैब एप बेस्ड कंपनियों की खुद की हैं। इस बीच, चालकों और कंपनियों के बीच चल रहा गतिरोध भी थमता नजर आया। उबर के एक अधिकारी ने बताया कि हड़ताली चालकों को मनाने की कोशिश जारी है। उनके साथ कई स्तर पर बातचीत जारी है। केजरीवाल सरकार और दिल्ली पुलिस से भी संपर्क साधा गया है।

साहिबाबाद में वैशाली में मेट्रो स्टेशन के सामने कार में तोड़फोड़ करते कैब चालक • उदयवीर सिंह

सुलह के लिए वार्ता जारी

सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि ओला से बातचीत चल रही है। उनके मुताबिक, रात में ड्यूटी करने से मना करने पर 500 रुपये जुर्माने को खत्म करने के साथ चिकित्सा और जीवन बीमा देने पर भी बातचीत करीब अंतिम चरण में है। इसी तरह छह रुपये प्रति किलोमीटर के किराये की जगह इसे बढ़ाकर 16 रुपये प्रति किलोमीटर करने के लिए कंपनियों ने कुछ दिन का समय मांगा है।

हड़ताली चालक उबर कैब न रोकें : हाई कोर्ट

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने हड़ताल करने वाले दो टैक्सी ड्राइवर यूनियन समेत अन्य चालकों और किसी भी हुड़दंगी को उबर कैब नहीं रोकने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंड लॉ ने सर्वोदय ड्राइवर एसोसिशन ऑफ दिल्ली और राजधानी टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि यूनियन और अन्य चालक उबर के कार्यालय के पास धरना भी नहीं दे सकते। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। अदालत एप बेस्ड कैब प्रदाता कंपनी उबर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका में उबर ने आरोप लगाया था कि सर्वोदय ड्राइवर एसोसिशन ऑफ दिल्ली और राजधानी टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन एवं अन्य हड़ताली चालक उबर कैब रोककर उनमें सवार यात्रियों को जबरदस्ती उतार रहे हैं। साथ ही कैब में से मोबाइल डिवाइस हटा दे रहे हैं। इससे उनका बिजनेस खराब हो रहा है और यह महिला सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के हिसाब से भी उचित नहीं है। याची का तर्क था कि दिल्ली-एनसीआर में बड़ी संख्या में चालक धरना दे रहे हैं। याचिका सोमवार की सुबह न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर के पास दायर की गई थी, जिनकी अनुमति के बाद सुनवाई के लिए इसे न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंड लॉ के पास भेजा गया था।

गिड़गिड़ाते रहे कार सवार
>> पेज 3

भारत का लगातार छठी सीरीज पर कब्जा

हैदराबाद टेस्ट में बांग्लादेश को 208 रन से हराकर भारत ने विराट कोहली की कप्तानी में लगातार छठी सीरीज जीत ली • प्रेट्र

संबंधित खबरें
>> पेज 16

जीत के शहंशाह कोहली

- लगातार छह टेस्ट सीरीज भारत ने पहली बार जीती
- इस दौरान 20 टेस्ट खेला भारत, 15 जीता, एक हारा, चार ड्रॉ रहे
- कोहली की कप्तानी में लगातार 19वें टेस्ट में भारत अजेय रहा
- इससे पहले गावस्कर की कप्तानी में भारत18 टेस्ट में अजेय रहा था

अजहर को पीछे छोड़ा

- अपनी कप्तानी में 14 टेस्ट जीतने वाले अजहर को पीछे छोड़ा
- कोहली से आगे सिर्फ गांगुली (21) और धौनी (27) हैं

सिर्फ पोंटिंग से पीछे

- इससे पहले अक्टूबर 2008 से जनवरी 2010 के दौरान लगातार पांच टेस्ट सीरीज जीता था भारत
- उस समय कुंबले, सहवाग और धौनी रहे थे भारत के कप्तान
- कप्तान के रूप में कोहली की 23वें टेस्ट में 15वीं जीत। उनसे आगे अब सिर्फ रिकी पोंटिंग (17)

धौनी से आगे निकले विराट

- धौनी ने लगातार सात अंतरराष्ट्रीय सीरीज जीती थीं, जबकि कोहली की यह 8वीं जीत है
- कोहली ने इंग्लैंड से वनडे और टी-20 सीरीज भी जीती है

3250 करोड़ से सुधरेगी दिल्ली की यातायात व्यवस्था

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जाम से जूझते दिल्लीवासियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने शहरी विकास निधि के तहत 3250 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इससे दिल्ली की यातायात व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। संयुक्त पुलिस आयुक्त अजय कश्यप ने बताया कि 1971 में सड़कों की कुल लंबाई 8380 किमी थी जो 2011 में 33,198 हो गई। हालांकि इस दौरान वाहनों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई। 1971 में दिल्ली में 2.17 लाख रजिस्टर्ड वाहन थे जो अब 90 लाख से अधिक हैं। वाहनों की बढ़ती संख्या जाम का सबसे बड़ा कारण है। ऐसे में केंद्र सरकारी की योजना से लोगों को जाम से राहत मिलने के आसार हैं।

शहरी विकास मंत्रालय ने शहरी विकास निधि के लिए जो 3250 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं उससे जाम वाली विभिन्न जगहें चिह्नित की जाएंगी। सड़कों की डिजाइन समेत जाम का वजहों को दूर किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो फ्लाईओवर, अंडरपास, फुट ओवरब्रिज का निर्माण होगा। द्वारका एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य तय समय में पूरा किया जाएगा। होलंबी कला और मुंडका में रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। रानी झांसी फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। इससे मध्य दिल्ली को जाम से राहत मिलेगी। भाग्य विहार और मीत विहार के पास टनल बनाया जाएगा। नरेला में रेलवे ओवर ब्रिज बनेगा।

देश में सबसे अधिक वायु प्रदूषण गुरुग्राम में

अनिल भारद्वाज • गुरुग्राम

शहर में वायु प्रदूषण के काले बादल लगातार बने हुए हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट में गुरुग्राम सोमवार को देश का सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करने वाला शहर बताया गया है। दस दिन पहले भी यही हालत थी।

सोमवार को सीपीसीबी की रिपोर्ट में देश के नौ शहरों का वायु प्रदूषण खतरे के मानक से ज्यादा दर्ज किया गया। गुरुग्राम सबसे ज्यादा प्रदूषित है। दूसरे स्थान पर बिहार का मुजफ्फरपुर और तीसरे स्थान पर उप्र का हरदोई बना हुआ है। गुरुग्राम में साढ़े चार माह से वायु प्रदूषण के काले बादल बने हुए हैं। इस दौरान कोई भी दिन ऐसा नहीं था, जब वायु प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान से कम दर्ज किया गया।

दस दिन पहले की स्थिति : 10 दिन पहले सेंट्रल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट में गुरुग्राम देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर था तो पटना दूसरे स्थान पर। तीसरे पर बिहार का शहर मुजफ्फरपुर व चौथे पर कानपुर और पांचवें स्थान पर आगरा बताया गया था।

सोमवार को वायु प्रदूषण का स्तर (पीएम 2.5)

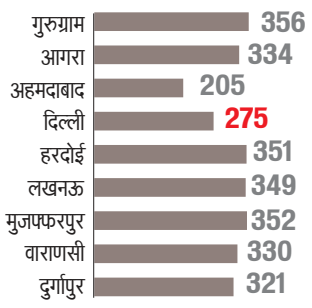

नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस, हुडा विभाग के साथ मिलकर जल्द एक योजना तैयार की जा रही है, जिसमें वायु प्रदूषण कम करने के समाधान तलाशे जाएंगे।

भूपेंद्र चौधरी, क्षेत्रीय अधिकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड

व्यापम घोटाला : 634 छात्रों का प्रवेश रद

नई दुनिया, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मप्र के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) घोटाले के दागी मेडिकल छात्रों को किसी भी तरह की राहत देने से इन्कार किया है। सोमवार को शीर्ष अदालत ने मप्र हाई कोर्ट के फैसले को यथावत रखते हुए मेडिकल में गलत तरीके से प्रवेश लेने वाले सभी 634 छात्रों के प्रवेश रद करने का आदेश दिया। इससे जुड़ी सभी अपील भी खारिज कर दीं। छात्रों ने आर्टिकल 142 के तहत राहत की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली जस्टिस केएम जोसेफ व जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने सुनवाई के बाद पिछले दिनों ही इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन छात्रों ने व्यापम के जरिये 2008 से 2012 के बीच मध्य प्रदेश के अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लिया था। अब इनमें से कई एमबीबीएस अंतिम वर्ष में हैं।

मप्र हाई कोर्ट के फैसले पर बंट गए थे सुप्रीम कोर्ट के जज : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को पहले सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ के सामने चुनौती दी गई। दोनों जजों ने अपने फैसले में माना था कि इन सभी छात्रों ने गलत तरीके से मेडिकल में प्रवेश लिया है, लेकिन इन सभी के प्रवेश को रद करने को लेकर उनकी राय बंट गई थी। जस्टिस जे. चेलामेश्वर ने कहा था कि इनमें से कई छात्रों की ज्यादातर पढ़ाई पूरी हो चुकी है। ऐसे में इनके प्रवेश को रद न करके इन्हें सेना में पांच साल तक मुफ्त में सेवा कराई जाए। पांच साल पूरे होने पर ही उन्हें डिग्री दी जाएगी। इस दौरान उन्हें केवल गुजारा भत्ता दिया जाएगा। वहीं जस्टिस अभय मनोहर सप्रे इससे असहमत थे। उनका कहना था कि गलत को गलत ही माना जाएगा। इसलिए सभी छात्रों के प्रवेश रद होने चाहिए। इसके बाद इस मामले को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ के सामने लाया गया।

क्या है अनुच्छेद 142 में : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को असीमित अधिकार दिए गए हैं। इसके तहत कोर्ट स्वविवेक से जनहित में कोई भी फैसला कर सकती है। मेडिकल छात्रों ने अनुच्छेद 142 को ही आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी। उन्होंने आग्रह किया था कि वे डॉक्टर बन चुके हैं, इसलिए समाजहित में उनका उपयोग किया जाए।

संबंधित खबरें
>> पेज 13

2008 से 2012 के बीच छात्रों ने मध्य प्रदेश में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में लिए थे दाखिले

फ्रॉड किया है, गलत तरीके से प्रवेश लिया है, कोई राहत नहीं दे सकते।
सुप्रीम कोर्ट

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस्तीफा दें : कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा है कि व्यापम घोटाले के भ्रष्टाचार पर अदालत के फैसले के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिन छात्रों का प्रवेश रद हुआ है उन्हें माफिया और अधिकारियों के गठजोड़ ने बड़ी राशि ले नकल करवाकर प्रवेश दिलाया था।

भ्रष्ट नेताओं के कारण छात्रों का भविष्य बर्बाद : आप

आप के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल ने कहा कि मंत्री व अफसरों के भ्रष्टाचार से 634 युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया, लेकिन गुनाहगार आजाद घूम रहे हैं। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, कांग्रेस नेता संजीव सक्सेना, व्यापम के पीयूष त्रिपाठी, नितिन मोहिंद्रा और सुधीर शर्मा जेल से बाहर हैं, लेकिन 634 छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया है।

शादी के बहाने पोलैंड की महिला से दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पोलैंड की रहने वाली एक 32 वर्षीय महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। क्रूज पर अपने साथ काम करने वाली महिला सहकर्मी का गौरव राणा ने लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया। 2 फरवरी को महिला शिकायत दर्ज कराने भारत आई। 11 फरवरी को वसंत कुंज थाना पुलिस ने गौरव के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया।

पटियाला हाउस कोर्ट की मजिस्ट्रेट अदालत में सोमवार को महिला ने न्यायाधीश के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। उसके वकील रोहित यादव ने बताया कि गौरव राणा फिलहाल फ्रांस में है। उसके वापस लौटने के बाद ही पुलिस उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई करेगी। एफआइआर के मुताबिक पीड़ित महिला और आरोपी गौरव एक ही क्रूज पर नौकरी करते थे। 2014 में उनकी पहली बार मुलाकात हुई और वे दोस्त बन गए। जल्द ही शादी का झांसा देकर गौरव ने पीड़ित महिला का शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। गौरव के बुलाने पर वर्ष 2015 में वह पहली बार भारत आई। आरोपी गौरव ने उसे शादी के परिप्रेक्ष में यहां अपने परिजनों से मिलाने का वादा किया था। मगर अब वह टाल मटोल करने लगा और महिला के पैसों से ही वह उसके साथ पूरे देश में घूमता रहा। महिला के वकील ने अदालत में आरोपी के साथ उसकी बातचीत के व्हाट्सअप रिकॉर्ड, फोन कॉल रिकॉर्ड, उसके ऊपर खर्च किए गए क्रेडिट व डेबिट कार्ड के रिकॉर्ड पेश किए हैं।

महिला के मुताबिक गौरव का रवैया देखकर उसने दूरी बना ली तो वह उसे लगातार शादी का झांसा देकर मनाता रहा। गौरव ने फरवरी 2016 में एक बार फिर एक पारिवारिक शादी में शामिल होने के बहाने फिर पीड़िता को भारत बुला लिया। यहां दिल्ली के महिपालपुर में एक किराये के घर में उसे रखा और उसके शारीरिक शोषण का क्रम जारी रहा। बाद में शक होने पर महिला ने अपने स्तर पर पता किया तो यह जानकर स्तब्ध रह गई कि गौरव ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड के भाई की शादी में बुलाया था और समारोह में उसे अपनी कजन सिस्टर बनाकर लोगों से मिलवाता रहा। इसके बाद अप्रैल में वह भारत से चली गई और अब गौरव पर मुकदमा करने के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया है।

वारदात

- महिला ने भारत में मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया बयान
- क्रूज पर हुई मुलाकात, आरोपी युवक फिलहाल फ्रांस में है

लाहौर में आत्मघाती हमला डीआइजी समेत 16 की मौत

लाहौर : पाकिस्तान के लाहौर में पंजाब प्रांत की विधानसभा के पास आत्मघाती हमले में पुलिस महानिरीक्षक (ट्रैफिक) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित 16 लोगों की मौत हो गई है। • पेज 15

सूखी बधाई से आंखें गीली

अभिषेक त्रिपाठी • नई दिल्ली

चिरप्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार ब्लाइंड टी-20 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम की आंखें सूखी बधाइयों से गीली हो गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, बीसीसीआइ, खेल मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सहित रितिक रोशन और शाह रुख खान जैसे फिल्म स्टारों ने टीम को बधाई दी, लेकिन लगातार दूसरी बार देश का नाम ऊंचा करने वाले इन खिलाड़ियों को इनाम के नाम पर कुछ नहीं मिला।

ओलंपिक और क्रिकेट विश्व कप ही नहीं, पैरालंपिक में भी पदक जीतने पर करोड़ों की धनवर्षा होती है, लेकिन ये विजेता अभागे साबित हुए हैं। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट और क्रिकेट एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड इन इंडिया के अध्यक्ष मयंतेश जी. ने कहा, 'हमने इन्हें सिर्फ तीन लाख की नकद राशि दी। कर्नाटक सरकार ने जरूर प्रदेश के दो खिलाड़ियों प्रकाश व सुनील को सरकारी नौकरी के साथ सात-सात लाख रुपये दिए हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को कुछ नहीं मिला। आंध्र प्रदेश के एथलीट के ओलंपिक में रजत जीतने पर केंद्र सरकार ही नहीं, दूसरे प्रदेश की सरकारें भी करोड़ों दे देती हैं, जबकि इस टीम को सिर्फ बधाई मिली। हम पीएम से मिलने की कोशिश कर रहे हैं।' लगातार दूसरी बार भारत में ब्लाइंड टी-20 विश्व कप कराने वाले मयंतेश ने कहा कि खेल मंत्रालय से 30 लाख की मदद मिली, लेकिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से सिर्फ आश्वासन मिला है। पिछले साल तत्कालीन बीसीसीआइ अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने एक करोड़ की मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन नहीं मिला। उन्होंने कहा, 'बीसीसीआइ और खेल मंत्रालय से हम मान्यता मांग रहे हैं। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका के ब्लाइंड संघों को वहां मान्यता मिल गई है, जिससे टीम को फिजियो, किट, यात्रा और अन्य मदद मिल जाती हैं। टूर्नामेंट में करीब 5.5 करोड़ लगे। हमने एक करोड़ का कर्ज लिया है। कुछ धन हमें प्रायोजकों से मिला, बाकी वेंडर्स से उधार लिया है।'

भेदभाव

- ब्लाइंड विश्व कप विजेता टीम को इनाम के नाम पर कुछ नहीं मिला
- बीसीसीआइ, मंत्रालय, रितिक और शाह रुख ने दी सिर्फ बधाई